



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 879]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 11, 2012/वैशाख 21, 1934

No. 879]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 11, 2012/VAISAKHA 21, 1934

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मई, 2012

का.आ. 1043(अ).—केन्द्रीय सरकार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) की धारा 20 की उप-धारा (3) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चयन समिति की सिफारिश पर दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवानिवृत्त), न्यायमूर्ति जितन्द्र मोहन मलिक को 2 मई, 2012 के पूर्वाहन से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा उनके 70 वर्ष की आयु को प्राप्त हो जाने तक, जो भी पहले हो, समय-समय पर यथासंशोधित उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 के साथ पठित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में निर्धारित निबंधनों और शर्तों पर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 1(3)/2010-सी पी यू (वाल्यूम II)]

मनोज परिदा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS FOOD AND
PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th May, 2012

S.O. 1043(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) read with sub-section (3) of Section 20 of the Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986), the Central Government, on the recommendation of the Selection Committee, hereby appoints Shri Justice Jatinder Mohan Malik (Retd.), Delhi High Court, as whole-time Member of the National Consumer Disputes Redressal Commission with effect from the forenoon of the 2nd day of May, 2012, for a period of five years, or until he attains the age of 70 years, whichever is earlier, on the terms and conditions prescribed in the Consumer Protection Act, 1986 read with the Consumer Protection Rules, 1987 as amended from time to time.

[F. No. 1(3)/2010-CPU (Vol. II)]

MANOJ PARIDA, Jt. Secy.